रहने वाले लाखों लोग वहां से भाग आये हैं; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ख) पाकिस्तान के संसाधनों तथा शस्त्रास्त्रों, अमरीका तथा चीन द्वारा पाकिस्तान को इन शस्त्रास्त्रों की सप्लाई में उनकी भूमिका सहित पाकिस्तान की सशस्त्र सेना के संबंध में स्थिति क्या है और इस स्थिति की तुलना में भारत की स्थिति क्या है?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) ऐसी सूचना मिली थी कि भारत-पाक सीमा के नजदीकी क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेना के जमाव और उसके आगे बढ़ने की कार्रवाई के कारण दोनों तरफ के सीमावर्ती गांवों के कुछ लोग अपने भीतरी क्षेत्रों में चले गए हैं। उनकी सही संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। सीमा पर तनाव कम होने पर उन लोगों के अपने गांवों को वापस लौटने की सूचना मिली है।

(ख) सामरिक दृष्टि से अमेरिका की नजरों में पाकिस्तान का बहुत महत्व हो गया है। पाकिस्तान की रक्षा सेनाओं के पास अत्याधुनिक शस्त्र-प्रणालियां हैं और अमेरिका तथा चीन दोनों देशों से ऐसे शस्त्रों की सप्लाई उसे जारी है।

सरकार ऐसी सभी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखती है जिनका हमारे राष्ट्र की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और पूर्ण रक्षा तैयारी सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर समुचित उपाय करती है।

Restructuring the Electronics Commission and the Department of Electronics

1037. SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is a scheme under Government's contemplation for restructuring the Electronics Commission and the Department of Electronics; and

(b) if so, what are the specific objectives of restructuring these bodies and the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE (SHRI K. R. NARAYANAN): (a) There is no scheme under Government's contemplation for restructuring the Electronics Commission and Department of Electronics, at present.

(b) Does not arise.

Seizure of foreign fishing trawlers by the Coast Gaurd

1038. SHRI SUBAS MOHANTY: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to news item which appeared in *The Statesman* dated the February 2, 1987 under the caption "Protecting Underwater Wealth";

(b) if so, what is the number of foreign fishing trawlers seized by the Coast Guard during 1986;

(c) what are the countries of their origin and whether their holds contained shrimp;

(d) whether there have been cases of Indian fishing boats being harassed by the Coast Guard; and

(e) if so, whether strict guidelines have been issued to the Coast Guard to ensure that harassment of interrupting of fishing activities of Indian boats does not take place?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI ARUN SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) 53.

(c) The countries of origin of the apprehended trawlers are Pakistan, Bangla Desh, Sri Lanka, Thailand, Taiwan and Korea. The custody of the apprehended trawlers, with their crew outfits and fish holds is made over to the local police.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के लिये योजना

1039. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके विभाग में देश के प्रत्येक कार्य के लिये योजना बनायी जाती है और इस प्रयोजनार्थ योजनाएं तैयार की जाती हैं, लेकिन अंग्रेजी के स्थान पर राजभाषा हिन्दी को लाने संबंधी ऐसी कोई योजना नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं पर आधारित पंचवर्षीय विकास योजनाएं योजना आयोग में बनाई जाती हैं । अंग्रेजी के स्थान पर राजभाषा हिन्दी को लाने संबंधी स्कीमें गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा तैयार की जाती हैं और संवीक्षा तथा पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल करने के वास्ते योजना आयोग को भेजी जाती हैं । राजभाषा का कार्य, राजभाषा अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाना है । इस प्रयोजन के लिए सातवीं योजना में परिव्यय 2 करोड़ रुपये है।

Representation from Riot Victims Association regarding payment of bank loans

1040. SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Reserve Bank of India, Central Office Bombay has received representation dated 31-1-1987 and also earlier representations from 'November 1984 Riot Victims Association, Janakpuri, New Delhi' regarding harassment being meted out by the Banks Managements for recovery of relief bank loans in lump sum from the riot victims who are not in a position to repay the loans;

(b) whether it is also a fact that Government have decided to recover the relief loans in lump sum from the riot victims through courts after initiating legal proceedings; and

(c) if so, what action has been taken by Government to remove the hardship being faced by the riot victims who are not in a position to repay the bank loans?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) Reserve Bank of India has reported that it has received a representation dated 31st January, 1987 from November 1984 Riot Victims Association on 12th February, 1987 regarding recovery of loans. It has advised its Regional Office at New Delhi to look into the complaints.

(b) and (c) Reserve Bank of India issued necessary guidelines to banks vide its circulars dated the 6th, 12th and 14th November, 1984 advising them to provide need-based loan assistance on comparatively softer terms and conditions to the affected persons in November, 1984 disturbances for continuing/re-establishing their production, business and occupation. It